

Title: Need to involve the MP(s) in the handpump allocations for the water problems in Uttar Pradesh.

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं ऐसा प्रश्न उठा रहा हूँ, जो पूरे हाउस के सभी सदस्यों से संबंधित है। भारत सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जिस पर विकास के लिए धन जिलों में जाता है, लेकिन किसी भी संसद सदस्य से उस पर कोई राय नहीं ली जा रही है। जैसे सुनिश्चित रोजगार योजना है, यहां से एक बार निर्देश भी गया था, लेकिन किसी भी लोक सभा या राज्यसभा के सदस्य से इस संबंध में कोई राय नहीं ली जा रही और यह जिला पंचायत, क्षेत्र विधायक को सौंपा जा रहा है।

महोदय, पेयजल की समस्या के लिए भारत सरकार से राज्य मिशन के कार्यक्रम के तहत पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50-50 हंड पम्प सारे विधायकों को दे दिए हैं- चाहे एमएलसी हो या एमएलए हो, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों को एक भी हंड पंप नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हं कि केन्द्र सरकार से जो पैसा पेयजल की समस्या पर जा रहा है, ... (व्यवधान) महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप मांग कर दीजिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने पीने के पानी का सवाल उठा दिया।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारे दो माननीय सदस्य चिन्मयानंद जी और भूगण सिंह जी यहां बैठे हैं। पूर्वांचल निधि में दो साल पहले संसद सदस्यों की सहमति से खर्चा होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा के 23 सदस्यों को पूर्वांचल निधि में कर दिया और हम लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी, किसी भी दल का सदस्य हो, वह पूर्वांचल निधि में पैसा नहीं दे सकता है। (व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि यह जो पैसा जा रहा है, उस पर हम लोगों का हस्तक्षेप होना चाहिए।